(c) the anticipated dates of completion of these projects?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA) : (a) There is no irrigation project under implementation by the Central Government. According to present policy irrigation projects are planned, investigated, formulated and implemented by the States concerned.

(b) and (c) Do not arise.

बाण सागर परियोजना

949. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाण सागर परियोजना के संबंध में हाल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सिंचाई मंत्रियों की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए तथा वर्तमान समय में इन राज्यों द्वारा पानी का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां । बाण सागर नियंत्रण बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक 24-8-92 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

(ख) बाण सागर बांध परियोजना के विभिन्न घटकों की प्रगति और वित्तीय स्थिति की पुनरीक्षा करने के बाद बोर्ड ने परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य की तारीख निम्नानुसार संशोधित की है :—

क्रेस्ट स्तर तक बांध—जून, 1995

द्वारों सहित बांध—जून, 1998

जैसा कि 1973 के बाण सागर समझौते में दिया गया है, बाण सागर परियोजना के जल को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों द्वारा 2 : 1 : 1 के अनुपात में बांटा जाना है ।

गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना

950. **श्री मोता पद्मनाभा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के बारे में प्राक्कलन इत्यादि सहित संशोधित आंकड़े केन्द्र सरकार को भेजे हैं;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा केन्द्र सरकार इस परियोजना को कब तक मंजूरी देगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि पोलावरम् परियोजना और गोदावरी नदी जल के संबंध में कोई अंतर्राज्यीय विवाद नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना को मंजूरी देने में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निर्दिष्ट टिप्पणियों और कमियों पर ध्यान दिए बिना जुलाई, 1990 में पहली रिपोर्ट का केवल अद्यतन अनुमान प्रस्तुत किया था और राज्य सरकार ने जुलाई, 1992 में पहली बार अंतिम रूप देने हेतु जल-विज्ञान अध्याय प्रस्तुत किया था ।

(ख) जांच के बाद केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जलवैज्ञानिक श्रृंखलाओं को अंतिम रूप दिया गया है और राज्य सरकार को सिंचाई आयोजना को अंतिम रूप देने की सलाह दी गयी है ताकि परियोजना घटकों के डिजाइन तैयार करने में सहायता मिल सके और लागत अनुमान तैयार किए जा सकें ।

(ग) और (घ) इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होने वाला जलमग्न क्षेत्र शामिल है । गोदावरी जल विवाद अधिकरण के आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को जलमग्नता के अंतर्गत आने वाले अपने अपने क्षेत्रों में भूमि और सम्पत्तियों की सुरक्षा अथवा उनके मुआवजे के लिए अपने विकल्प बताने अपेक्षित हैं । आन्ध्र प्रदेश सरकार को दोनों राज्य सरकारों

से विकल्प प्राप्त करने अपेक्षित हैं । राज्य सरकार को पर्यावरण और वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी भी अपेक्षित है ।

Construction of S. Y. L. Canal

951. SHRI S. S. SURJEWALA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 723 given in the Rajya Sabha on the 28th February, 1992 and state :

(a) whether it is a fact that the construction of Sutlej Yamuna Link canal in the Punjab territory was handed over to Border Roads Organisations, if so, the progress made in this behalf, if not, what steps are being taken to ensure the construction of the canal;

(b) whether Government are aware that the portion of the canal already constructed in Punjab and Haryana have been badly damaged on account of its non-use, if so, the amount of loss incurred so far;

(c) how much amount has been incurred by the State of Haryana for its construction and the amount of loss occurred to the State of Haryana so far due to non-completion of the canal; and

(d) how much more time would be taken to complete it and make it operational ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA) : (a) No, Sir. The Government of Punjab has already been advised to engage appropriate agency/agencies to complete the balance works. Chief Minister, Punjab has been addressed by the Minister (Water Resources) requesting him to expeditiously take all necessary steps required to resume the work.

(b) Yes, certain portions of SYL Canal already constructed in the Punjab and Haryana territories have been demaged on account of its non-use and due to floods in September, 1988. The extent of demages in SYL Canal, both in Haryana and Punjab have not been assessed by the State Governments.

(c) As per the information furnished by Government of Haryana, an expenditure of about Rs. 40 crores has been incurred on construction of SYL Canal in Haryana upto March, 1991. As estimated by the State Government, Haryana is losing incremental agricultural production of over 8 lakh tonnes per annum amounting to more than Rs. 100 crores due to non-completion of the canal.

(d) The time schedule for completing the project will depend upon the nature and capacity of the new agency/agencies to be engaged by Government of Punjab.

Central Assistance for Inter-State Water Projects

952. SHRI AJIT P. K. JOGI : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what is the number of inter-State water projects which would be catered by the Madhya Pradesh Government;

(b) whether Government would provide assistance in order to complete these inter-State projects;

(c) if so, the amount sanctioned so far; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA) : (a) Madhya Pradesh is a participating State in seven inter-State Ongoing Major Irrigation/Multipurpose Projects namely Bansagar, Rajghat, Urmil, Bawanthadi, Barriyarpur Left Bank Canal, Sardar Sarover and Indira Sagar (Narmada Sagar).

(b) to (d) According to present policy Central assistance is given in the form of block grants and loans to the State Governments. It is for the participating States to provide adequate funds annually as per priority and agreements entered into for implementation of inter-State Projects.